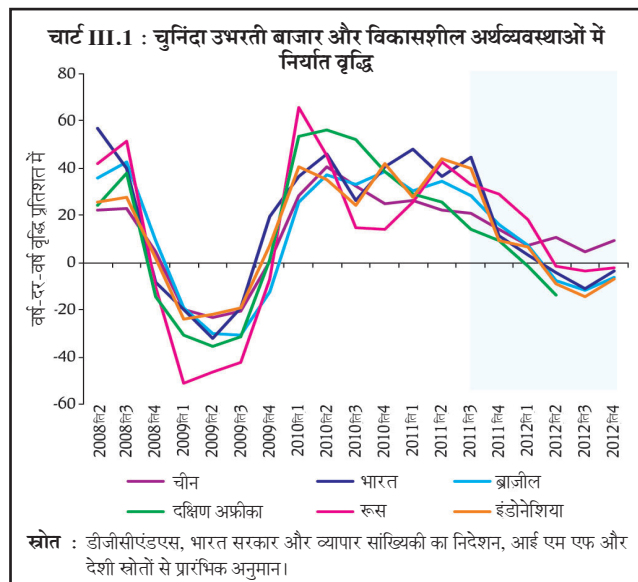


III. बाह्य क्षेत्र

2012-13 की ति2 में चालू खाते का घाटा (सीएडी)-जीडीपी अनुपात 5.4 प्रतिशत के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया जिससे सीएडी की दीर्घकालिकता और वित्तपोषण संबंधी चिंता बढ़ गई। बदतर होता जा रहा व्यापार घाटा और सेवा निर्यात की मंद वृद्धि सीएडी में तेज वृद्धि होने के प्रमुख कारक थे। दुर्बल बाह्य मांग, जिसने पण्य निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, के साथ पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई वाले पदार्थ (पीओएल) तथा स्वर्ण के निरंतर उच्च आयात ने 2012-13 की ति3 में व्यापार संतुलन की स्थिति खराब कर दी। सरकार द्वारा नीतिगत पहलें करने के बावजूद, निर्यात में सुधार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में आर्थिक सुधार पर निर्भर है। सीएडी के वित्तपोषण के लिए पूंजी प्रवाह इस समय पर्याप्त होने के बावजूद इससे जुड़ी अस्थिरता बाह्य क्षेत्र पर दबाव बना सकती है। स्पष्ट रूप से, यह अनिवार्य है कि सीएडी को कम किया जाए और इस बीच इसका विवेकपूर्ण वित्तपोषण भी किया जाए।

दुर्बल बाह्य मांग पण्य निर्यात पर निरंतर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है

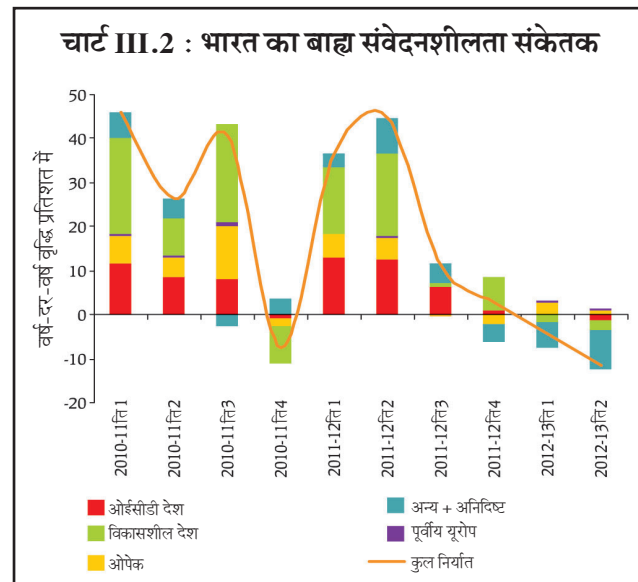
III.1 भारत का निर्यात निष्पादन निरंतर कम वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव और उन्नत तथा प्रमुख ईएमडीई में



अनिश्चितता को दर्शाता रहा। उन्नत तथा ईएमडीई में वैश्विक विनिर्माण चक्र में गिरावट ने संपूर्ण विश्व के व्यापार की मात्रा को प्रभावित किया जो कि भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित प्रमुख ईएमडीई की ऋणात्मक निर्यात वृद्धि से दिखता है (चार्ट III.1)। चीन की निर्यात वृद्धि सकारात्मक बनी रहने के बावजूद हाल की अवधि में इसमें गिरावट हुई है।

नीतिगत कार्रवाई के बावजूद निर्यात वृद्धि का पुनरुज्जीवन अनिश्चित बना हुआ है

III.2 2011-12 की दूसरी छमाही में शुरू हुआ भारत का मंद निर्यात निष्पादन 2012-13 में अब तक और भी मंद हो गया। वैश्विक वृद्धि की संभावना दुर्बल बनी रहने से निर्यात का पिछले वर्ष के स्तर पर पहुंचना भी मुश्किल है। पण्यवार आंकड़े दर्शाते हैं कि इंजीनियरिंग माल, पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, रत्न और आभूषण तथा रसायन और संबंधित उत्पाद की निर्यात वृद्धि गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी क्योंकि अमरीका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में मांग की स्थिति मंद बनी हुई थी। विविधता लाने के प्रयासों के अंतर्गत खोजे गए निर्यात के नए गंतव्यों से हुई मांग में भी मंदी देखी गई। उदाहरण के लिए, विकसित देशों को हुए निर्यात में वृद्धि के अलावा विकासशील देशों को हुए निर्यात की वृद्धि में भी हाल की तिमाहियों में या तो कमी आई या उसमें गिरावट आई (चार्ट III.2)। अप्रैल-नवंबर 2012 के दौरान पण्य निर्यात में हुई गिरावट में यूरोपीय संघ का हिस्सा 27.4 प्रतिशत था जिसके बाद सिंगापुर (21.0 प्रतिशत),



चीन (20.7 प्रतिशत), हांग कांग (4.8 प्रतिशत) और इंडोनेशिया (4.6 प्रतिशत) का स्थान था। वैश्विक सुधार में कमी से निर्यातमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में कम वृद्धि का असर इन देशों से भारत को होने वाली बाह्य मांग पर भी पड़ा।

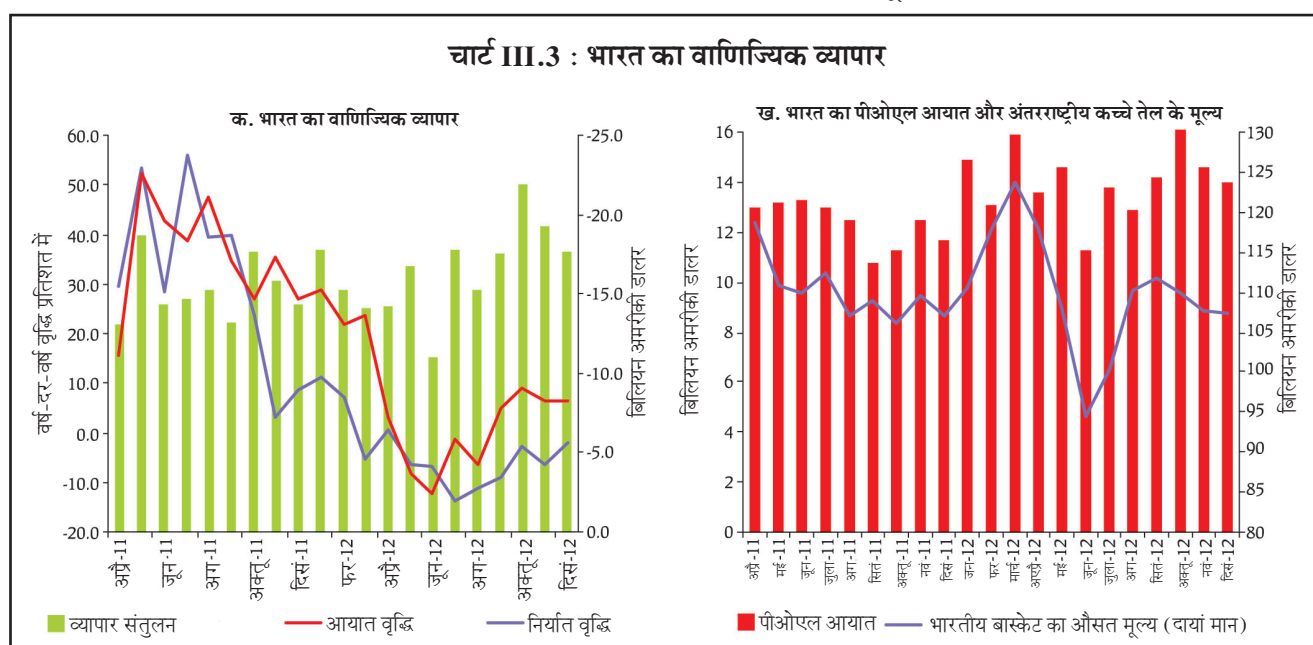
III.3 निर्यात क्षेत्र के मंद निष्पादन को देखते हुए सरकार ने 26 दिसंबर 2012 को निर्यात संवर्धन के उपायों की घोषणा की जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं (i) चुनिंदा रोजगारोन्मुख क्षेत्रों के लिए ब्याज रियायत योजना को मार्च 2014 के अंत तक बढ़ाना, (ii) सार्क क्षेत्र के देशों, अफ्रीका और म्यांमार के लिए एक्विजि बैंक के माध्यम से 2 प्रतिशत ब्याज राहत की प्रायोगिक योजना शुरू करना, (iii) फोकस बाजार योजना, विशेष फोकस बाजार योजना और बाजार-संबद्ध फोकस उत्पाद योजना का दायरा बढ़ाना और (iv) आधार अवधि की तुलना में जनवरी-मार्च 2013 में अमरीका, यूरोपीय संघ और एशियाई देशों को वृद्धिशील निर्यात के लिए प्रोत्साहन। निर्यात क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में वृद्धिशील पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण को सहायता देने के लिए 14 जनवरी 2013 को अनुसूचित बैंकों के लिए अमरीकी डॉलर-रुपया स्वैप योजना शुरू की। इन उपायों के बावजूद प्रमुख व्यापारी सहभागियों को निर्यात में शीघ्र सुधार तब तक नहीं हो सकेगा जब तक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और ईएमडीई में आर्थिक गतिविधियों में तेजी न आ जाए।

पीओएल और स्वर्ण के निरंतर उच्च आयात से भारत का व्यापार घाटा और बढ़ सकता है

III.4 आयात वृद्धि में सितंबर 2012 से तेजी आई जिसका मुख्य कारण पीओएल की मात्रा में वृद्धि था (चार्ट III.3)। स्वर्ण के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में हाल के महीनों में हुई वृद्धि के चलते हाल के महीनों में स्वर्ण का आयात उच्च स्तर पर बना रहा। दूसरी ओर तेल से भिन्न और स्वर्ण से भिन्न आयात में गिरावट आई जो कि देशी आर्थिक गतिविधियों में मंदी को दर्शाती है।

III.5 सितंबर 2012 से आयात वृद्धि सकारात्मक हो जाने और निर्यात वृद्धि मंद बनी रहने से व्यापार घाटे की स्थिति खराब होने की संभावना बढ़ गई। अप्रैल-दिसंबर 2012 के दौरान व्यापार घाटा अप्रैल-दिसंबर 2011 की तुलना में 7.2 प्रतिशत अधिक था (सारणी III.1)। आगे, वैश्विक और देशी वृद्धि की स्थिति के अलावा पीओएल और स्वर्ण आयात की प्रवृत्ति भारत के समग्र व्यापार घाटे की मुख्य निर्धारक होगी।

III.6 चालू खाता और समष्टि-वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए स्वर्ण आयात को कम करने की आवश्यकता के संदर्भ में अब तक के नीतिगत प्रयासों का लक्ष्य स्वर्ण कारोबार के वास्तविक हित में और मुद्रास्फीति के प्रति बचतकर्ताओं की प्रतिरक्षा के बीच संतुलन बनाना था। हाल के वर्षों में स्वर्ण की मांग सट्टेबाजी के प्रयोजन से भी बढ़ गई थी। इस पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक ने भारत में स्वर्ण और



सारणी III.1 भारत का वणिक् व्यापार

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अप्रैल-मार्च				अप्रैल-दिसंबर			
	2010-11 (सं)		2011-12 (अ)		2011-12 (सं)		2012-13 (अ)	
	राशि	वृद्धि (%)	राशि	वृद्धि (%)	राशि	वृद्धि (%)	राशि	वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्यात	251.1	40.5	306.0	21.8	226.6	29.6	214.1	-5.5
जिसमें से : तेल	41.5	47.1	56.0	35.1	42.3	49.5	40.0	-5.4
तेल से इतर	209.7	39.3	249.9	19.2	184.3	25.8	174.1	-5.5
सोना	6.1	39.6	6.7	10.8	5.0	31.6	4.7	-6.0
तेल से इतर और सोना से इतर	203.6	39.2	243.2	19.5	179.3	25.6	169.4	-5.5
आयात	369.8	28.2	489.3	32.3	363.9	35.2	361.3	-0.7
जिसमें से : तेल	106.0	21.6	155.0	46.2	111.0	47.6	125.4	13.0
तेल से इतर	263.8	31.1	334.4	26.7	252.9	30.4	235.9	-6.7
सोना	40.5	41.6	56.3	38.9	41.7	46.3	37.8	-9.4
तेल से इतर और सोना से इतर	223.3	29.4	278.0	24.5	211.2	27.6	198.1	-6.2
व्यापार घाटा	-118.6		-183.4		-137.3		-147.2	
जिसमें से : तेल	-64.5		-98.9		-68.7		-85.4	
तेल से इतर	-54.1		-84.4		-68.6		-61.8	
तेल से इतर और सोना से इतर	-19.7		-34.8		-31.9		-28.7	
ज्ञापन :								
व्यापार घाटा / जीडीपी (प्रतिशत में)		-7.0		-10.0		-10.1		-11.7

सं : संशोधित।

अ : अनंतिम।

एनबीएफसी द्वारा स्वर्ण ऋण संबंधी मुद्दों के अध्ययन हेतु कार्य दल (अध्यक्ष: श्री के.यू.बी.राव) गठित किया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अधिक स्वर्ण आयात से बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इस दल ने स्वर्ण मांग को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की। इसमें स्वर्ण-समर्थित नए वित्तीय उत्पादों की शुरुआत, वर्तमान स्क्रेप स्वर्ण की आपूर्ति के चैनलीकरण जैसे आपूर्ति प्रबंधन उपाय और स्वर्ण से संबंधित साधनों पर कर प्रोत्साहन और स्वर्ण के मौद्रिकरण को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने संबंधितों और जनता की टिप्पणियों के लिए इस रिपोर्ट को 2 जनवरी 2013 को अपनी वेबसाइट पर डाला है।

III.7 सरकार ने स्वर्ण आयात पर सीमा शुल्क को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने के अलावा, पारस्परिक निधियों द्वारा ईटीएफ के अंतर्गत भौतिक रूप से रखे गए स्वर्ण के एक भाग को जारी करने और स्वर्ण को स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत बैंकों में जमा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। स्वर्ण जमा की न्यूनतम मात्रा और अवधि को कम किया गया है (3 वर्ष से 6 माह)।

2012-13 की ति2 में सीएडी-जीडीपी अनुपात ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच जाने से सीएडी की व्यवहार्यता के प्रति चिंता उत्पन्न हो गई है

III.8 भारत का चालू खाते का खाता (सीएडी) 2012-13 की ति 2 में और अधिक बढ़ गया जिसका मुख्य कारण व्यापार घाटे की स्थिति और खराब हो जाना, निवल सेवा निर्यात की मंद वृद्धि और प्राथमिक आय के अंतर्गत उच्च बहिर्वाह था (सारणी III.2)। 5.4 प्रतिशत पर सीएडी-जीडीपी अनुपात न सिर्फ व्यवहार्य नहीं है बल्कि यह अब तक का सर्वोच्च स्तर भी है। प्रारंभिक संकेत दर्शाते हैं कि 2012-13 की ति3 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीएडी इस स्तर से और भी बढ़ सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंद वृद्धि की स्थिति से हाल की तिमाहियों में भारत के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात की वृद्धि प्रभावित हुई है। किंतु प्रमुख आईटी फर्मों के 2012-13 की ति3 के परिणाम उनके डॉलर राजस्व में कुछ सुधार दर्शाते हैं। 2013 में वैश्विक आईटी व्यय में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान के बावजूद वैश्विक सुधार संबंधी अनिश्चितता

सारणी III.2 : भारत के भुगतान संतुलन की प्रमुख मदे

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

	2011-12 (आंस)	2011-12				2012-13	
		ति1 (आंस)	ति2 (आंस)	ति3 (आंस)	ति4 (आंस)	ति1 (आंस)	ति2 (प्रा)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. वस्तुओं का निर्यात	309.8	78.8	79.6	71.5	80.0	76.7	69.8
2. वस्तुओं का आयात	499.5	123.7	124.1	120.1	131.7	119.0	118.2
3. व्यापार संतुलन (1-2)	-189.7	-44.9	-44.5	-48.6	-51.7	-42.3	-48.3
4. सेवाओं का निर्यात	140.9	33.7	32.3	37.3	37.7	34.8	34.8
5. सेवाओं का आयात	76.9	17.4	18.3	21.1	20.0	20.8	19.2
6. निवल सेवाएं (4-5)	64.0	16.3	14.0	16.1	17.7	14.0	15.7
7. वस्तुओं और सेवाओं का संतुलन (3+6)	-125.7	-28.6	-30.5	-32.5	-34.0	-28.3	-32.8
8. प्राथमिक आय (निवल)	-16.0	-3.6	-4.0	-3.8	-4.6	-4.9	-5.6
9. द्वितीयक आय (निवल)	63.5	14.8	15.6	16.2	16.9	16.8	16.1
10. निवल आय (8+9)	47.5	11.2	11.6	12.4	12.3	11.9	10.5
11. चालू खाता शेष (7+10)	-78.2	-17.4	-18.9	-20.2	-21.7	-16.4	-22.3
12. पूंजी खाता शेष	-0.1	-0.3	0.2	0.1	-0.2	-0.2	-0.3
13. वित्त लेखा शेष	80.7	18.7	19.0	20.6	22.4	15.7	24.2
जिसमें से : रिज़र्व में परिवर्तन ((-) वृद्धि/(+) कमी)	12.8	-5.4	-0.3	12.8	5.7	-0.5	0.2
14. भूल-चूक (11+12+13) जापान मदे (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	-2.4	-0.9	-0.4	-0.5	-0.6	1.0	-1.6
15. व्यापार शेष	-10.3	-9.8	-9.9	-10.7	-10.6	-10.0	-11.7
16. निवल सेवाएं	3.5	3.6	3.1	3.5	3.6	3.3	3.8
17. निवल आय	2.6	2.4	2.6	2.7	2.5	2.8	2.5
18. चालू खाता शेष	-4.2	-3.8	-4.2	-4.4	-4.5	-3.9	-5.4
19. पूंजी और वित्त लेखा, निवल (रिज़र्व में परिवर्तन को छोड़कर)	3.7	5.2	4.4	1.7	3.4	3.8	5.7

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि उप घटकों का जोड़ समग्र से मेल न खाता हो।

आंस : आंशिक रूप से संशोधित। प्रा. : प्राथमिक।

भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए अधोमुखी जोखिम बनी हुई है। जब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं होता और भारत के माल और सेवा निर्यात में तेजी नहीं आती, तब तक उच्च सीएडी निरंतर चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।

मजबूत पूंजी प्रवाहों ने सीएडी के वित्तपोषण में सहायता दी

III.9 भुगतान संतुलन के आंकड़े दर्शाते हैं कि पूंजी प्रवाह में सुधार 2012-13 की ति2 के दौरान बढ़ रहे सीएडी के वित्तपोषण के लिए लगभग पर्याप्त था जैसा कि विदेशी मुद्रा भंडार के किए गए कुछ ही आहरण से स्पष्ट हो जाता है (सारणी III.3)।

III.10 जहां एफडीआई के अंतर्गत के निवल अंतर्वाह अप्रैल-नवंबर 2012 के दौरान कुछ कम हो गए, वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के निवल अंतर्वाहों से ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति पता चली। 2012-13 (18 जनवरी तक) के दौरान के 18.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवल एफआईआई अंतर्वाह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (7.6 बिलियन

अमरीकी डॉलर) काफी अधिक थे जिससे सीएडी के वित्तपोषण में अस्थायी राहत मिली थी (सारण III.4)।

III.11 वैश्विक चलनिधि और दृष्टिकोण में सुधार होने के अलावा मजबूत एफएफआई अंतर्वाह का मुख्य कारण सरकार द्वारा सितंबर 2012 से घोषित हाल के सुधारों से प्रेरित देशी अर्थव्यवस्था संबंधी धारणा में सुधार था। इन सुधारों में अन्य के अलावा खुदरा, बीमा और पेंशन क्षेत्रों के लिए उदारीकृत एफडीआई मानदंड, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की योजना और कंपनी तथा सरकारी ऋण बाजारों में एफआईआई सीमा में वृद्धि शामिल है। सरकारी प्रतिभूतियों और कंपनी बांडों में एफएफआई में से प्रत्येक की सीमा 5 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ा दी गई जिससे देशी ऋण में कुल निवेश सीमा (इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनी ऋण सहित) 75 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। जहां इस बढ़ी हुई सीमा से ऋण अंतर्वाह में वृद्धि हो सकती है, वहीं ये सीएडी के वित्तपोषण के लिए कोई मजबूत आधार उपलब्ध नहीं कराते।

सारणी III.3 : वित्तीय लेखा की अलग-अलग मदें

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

1	2011-12 (आंस)	2011-12				2012-13	
		ति1 (आंस)	ति2 (आंस)	ति3 (आंस)	ति4 (आंस)	ति1 (आंस)	ति2 (प्र.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. प्रत्यक्ष निवेश (निवल)	22.1	9.3	6.5	5.0	1.4	3.9	8.9
1.क भारत को प्रत्यक्ष निवेश	33.0	12.4	9.5	6.9	4.2	5.9	10.3
1.ख भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	-10.9	-3.1	-3.0	-1.9	-2.9	-2.0	-1.4
2. संविभाग निवेश (निवल)	16.6	2.3	-1.4	1.8	13.9	-2.0	7.6
2.क भारत में संविभाग निवेश	16.8	2.5	-1.6	1.9	14.1	-1.7	7.9
2.ख भारत द्वारा संविभाग निवेश	-0.2	-0.2	0.2	-0.05	-0.2	-0.3	-0.3
3. वित्तीय डेरिवेटिव एंड कर्मचारी स्टॉक विकल्प	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	-0.5	-0.3
4. अन्य निवेश (निवल)	29.2	12.6	14.2	1.0	1.4	14.8	7.9
4.क अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0.6	0.3	0.2	0.1	0.03	0.1	0.1
4.ख मुद्रा और जमाराशियां	12.1	1.2	3.1	3.2	4.6	6.4	3.5
जमाराशियां लेने वाले निगम, केंद्रीय बैंक को छोड़कर (एनआरआई जमाराशियां)	11.9	1.2	2.8	3.3	4.7	6.6	2.8
4.ग ऋण*	16.8	14.9	9.5	-7.7	-0.03	3.5	3.3
4.ग.ि भारत को ऋण	15.7	14.9	8.9	-8.1	-0.02	3.4	3.6
जमाराशियां लेने वाले निगम, केंद्रीय बैंक को छोड़कर	4.1	11.5	3.9	-8.7	-2.6	3.0	2.0
सामान्य सरकारी (बाह्य सहायता)	2.5	0.4	0.3	1.4	0.3	0.02	0.1
अन्य क्षेत्र (बाह्य वाणिज्यिक उधार)	9.1	3.0	4.7	-0.8	2.3	0.4	1.4
4.ग.ii भारत द्वारा ऋण	1.0	-0.02	0.6	0.5	-0.01	0.1	-0.3
सामान्य सरकारी (बाह्य सहायता)	-0.2	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.1	-0.1
अन्य क्षेत्र (बाह्य वाणिज्यिक उधार)	1.2	0.02	0.6	0.5	0.03	0.1	-0.3
4.घ व्यापार ऋण और अग्रिम	6.7	3.1	2.9	0.6	0.2	5.4	4.1
4.ङ अन्य खाते, प्राप्य/देय	-6.9	-6.8	-1.5	4.8	-3.3	-0.6	-3.0
5. रिज़र्व आस्तियां (वृद्धि/ कमी+)	12.8	-5.4	-0.3	12.8	5.7	-0.5	0.2
वित्तीय लेखा (1+2+3+4+5)	80.7	18.7	19.0	20.6	22.4	15.7	24.2

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि उप घटकों का जोड़ समग्र से मेल न खाता हो।

प्रा.: प्राथमिक आंस: आंशिक रूप से संशोधित - : उपलब्ध नहीं

*: इसमें बाह्य सहायता, बाह्य वाणिज्यिक उधार और गैर-अनिवासी भारतीयों की बैंकिंग पूंजी एवं अल्पावधि व्यापार ऋण शामिल हैं।

III.12 सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत हाल का अधिकतर एफआईआई निवेश अल्पकालिक खजाना बिलों में चला गया जिससे बाह्य ऋण का पुनर्वित्त जोखिम बढ़ गया। दूसरी ओर,

मूल्यहास के दौर के बाद दायराबद्ध मुद्रा से भारतीय बाजार एफआईआई के लिए आकर्षक हो गया। आगे, देशी सुधारों को लागू करना और बढ़ाना अर्थव्यवस्था को इक्विटी प्रवाह की निरंतरता बनी रहने के लिए आवश्यक होगा। पिछली तिमाही में वैश्विक बाजारों में जोखिम में कमी आने के बावजूद यूरो क्षेत्र के जोखिम के कारण पूंजी प्रवाहों में अस्थिरता हो सकती है।

सारणी III.4 : पूंजी प्रवाह

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

घटक	2011-12				2012-13		
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
	मासिक प्रवाह का औसत						
1	2	3	4	5	6	7	8
भारत में एफडीआई	4.1	3.1	2.3	1.5	2.0	3.4	1.9*
भारत द्वारा एफडीआई	1.0	1.0	0.6	1.0	0.7	0.5	0.9*
एफआईआई	0.8	-0.5	0.6	4.7	-0.6	2.6	3.3
डीआर/जीडीआर	0.1	0.1	0.03	0.01	0.03	0.03	0.0
ईसीबी	1.0	1.6	-0.3	0.8	0.1	0.5	1.3
एनआरआई	0.4	0.9	1.1	1.6	2.2	0.9	0.9*

*: अक्तूबर-नवंबर.

III.13 अनिवासी भारतीयों ने उच्च ब्याज दर और कमजोर होते रूप से लाभ लेते हुए भारत स्थित बैंकों में अपनी जमाराशि को अप्रैल-नवंबर 2011-12 की तुलना में 2012 की इसी अवधि में लगभग दोगुना कर दिया। भारतीय कंपनी क्षेत्र द्वारा मूल धन की उच्च चुकौती के बावजूद बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से निवल प्रवाह 2012-13 की ति3 में पिछली तिमाही की तुलना में अधिक थे। ईसीबी को मुख्यतः

पूँजीगत माल के आयात, नई परियोजनाओं और एफसीसीबी के शोधन के लिए जुटाया गया था।

अक्टूबर और नवंबर के मूल्यहास के बाद दिसंबर 2012 में रुपया विनिमय दर दायराबद्ध रही

III.14 सरकार द्वारा घोषित सुधार के विभिन्न उपायों और जोखिम उठाने की वैश्विक स्तरीय इच्छा में वृद्धि के चलते रुपए में सितंबर 2012 में सुधार हुआ। किंतु उच्च सीएडी संबंधी चिंताओं की चुनौती और देशी वृद्धि संबंधी अनिश्चितता के कारण अक्टूबर और नवंबर 2012 के दौरान रुपए में पुनः गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई और बाद में दिसंबर में यह दायराबद्ध (₹54.2-55.1 प्रति अमरीकी डॉलर) रहा। सांकेतिक संदर्भ में रुपए की प्रवृत्ति दर्शाते हुए 6 मुद्राओं और 36 मुद्राओं पर आधारित आरईआई में मार्च 2012 के अंत की तुलना में 18 जनवरी 2013 को क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ (सारणी III.5)।

बाह्य ऋण में 2012-13 की ति2 में तेज वृद्धि हुई

III.15 सितंबर 2012 के अंत में भारत का बाह्य ऋण पिछली तिमाही की तुलना में काफी अधिक था जिसमें ऋण के दीर्घकालिक और अल्पकालिक - दोनों घटकों में वृद्धि हुई थी (सारणी III.6)। विशेष रूप से अनिवासी बाह्य रुपया मूल्यवर्गित जमा (एनआरआई) में तेज वृद्धि हुई थी जिससे बेहतर प्रतिलाभ और रुपया मूल्यहास के कारण अनिवासियों द्वारा निरंतर दिलचस्पी दिखाने का पता चलता है।

सारणी III.5 : सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर - व्यापार आधारित (आधार : 2004-05 = 100)

	सूचकांक 18 जनवरी 2013 (अ)	वर्ष-दर-वर्ष-घट-बढ़ (औसत) 2011-12	वित्तीय वर्ष घट-बढ़ (मार्च 2012 के अंत की तुलना में 18 जनवरी 2013)
1	2	3	4
36- रीर	91.7	-3.2	-3.9
36-नीर	78.9	-6.4	-4.9
6-रीर	105.7	-6.8	-3.5
6-नीर	75.8	-7.9	-5.2
₹/अम.डॉ. (मार्च के अंत में)	53.9*	-12.7	-5.0*

नीर : सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर।

रीर : वास्तविक प्रभावी विनिमय दर।

अ : अर्न्तम। * : 24 जनवरी 2013 के यथास्थिति।

टिप्पणी: सूचकांक में वृद्धि रुपए के मूल्य में वृद्धि की ओर संकेत करती है एवं सूचकांक में कमी रुपए के मूल्य में कमी की ओर संकेत करती है।

सारणी III.6 : भारत का बाह्य ऋण

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

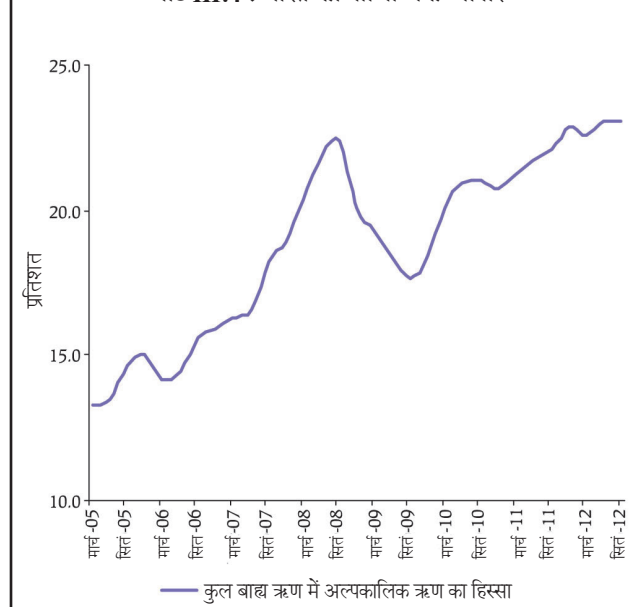
मद	मार्च 2011 के अंत में (आंस)	मार्च 2012 के अंत में (आंस)	जून 2012 के अंत में (आंस)	सितंबर 2012 के अंत में (त्व. अ.)	जून 2012 के अंत की तुलना में सितंबर 2012 के अंत का घट-बढ़
	कीमत				प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1. बहुपक्षीय	48.5	50.5	49.7	50.7	2.0
2. द्विपक्षीय	25.7	26.7	27.1	27.6	1.7
3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	6.3	6.2	6.0	6.1	1.6
4. व्यापार ऋण (1 वर्ष से ऊपर)	18.6	19.0	19.0	19.0	3.0
5. बाह्य वाणिज्यिक उधार	88.5	104.9	104.3	109.0	4.6
6. एनआरआई जमाराशियां	51.7	58.6	60.9	67.0	10.1
7. रुपया ऋण	1.6	1.4	1.2	1.3	6.8
8. दीर्घावधि (1 से 7)	240.9	267.2	268.3	280.8	4.7
9. अल्पावधि (मूल परिपक्वता)	65.0	78.2	80.5	84.5	5.0
10. दीर्घावधि (अवशिष्ट परिपक्वता)#	129.1	147.4	150.0	159.6	6.4
कुल (8+9)	305.9	345.4	348.8	365.3	4.7

आंस: आंशिक रूप से संशोधित त्व.अ: त्वरित अनुमान #: आरबीआई अनुमान

अल्पकालिक ऋण के अधिक हिस्से से बाह्य ऋण की संरचना में परिवर्तन आया

III.16 बाह्य ऋण की संरचना में अल्पकालिक ऋण के हिस्से में वित्तीय संकट के तुरंत बाद की अवधि में गिरावट आने के बाद

चार्ट III.4 : भारत का वाणिज्यिक व्यापार



हाल की अवधि में उसमें वृद्धि हो रही है (चार्ट III.4)। वित्तीय संकट के तुरंत बाद की अवधि में गिरावट का मुख्य कारण अल्पकालिक व्यापार ऋण में कमी आना था। यह प्रवृत्ति उलटी होने का कारण अल्पकालिक व्यापार ऋण में तथा सरकारी खजाना बिलों और कुछ अन्य लिखतों में एफआईआई निवेश में वृद्धि होना था।

बाह्य संवेदनशीलता संकेतकों ने 2012-13 की ति2 में संमिश्र प्रवृत्ति दर्शाई

III.17 2012-13 की ति2 में बाह्य संवेदनशीलता संकेतकों की प्रवृत्ति संमिश्र थी। जहां जीडीपी-बाह्य ऋण का अनुपात (रूपया संदर्भ में गणना किया गया) में कुछ सुधार दिखा, वहीं बाह्य ऋण-अल्प कालिक ऋण अनुपात (मूल परिपक्वता) पिछली तिमाही के स्तर पर बना रहा। किंतु बाह्य ऋण-विदेशी मुद्रा भंडार अनुपात में गिरावट आई (सारणी III.7)।

III.18 निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं के रूप में भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय स्थिति (एनआईआईपी) जून 2012 के अंत के 223.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर सितंबर 2012 के अंत में 271.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। निवल देयता में वृद्धि होने का मुख्य कारण देयताओं में काफी वृद्धि होना और

सारणी III.8 : भारत के समग्र अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

अवधि	मार्च-11	मार्च-12	जून-12	सित-12
1	2	3	4	5
एनआईआईपी	-203.6	-248.4	-223.8	-271.5
आसिययां	439.8	437.8	433.7	441.7
देयताएं	643.4	686.2	657.6	713.2
एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात*	-12.1	-13.5	-12.3	-15.3

* वार्षिकीकृत सकल देशी उत्पाद पर आधारित।

'-' निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं से तात्पर्य है।

विनिमय दर की घट-बढ़ से उत्पन्न मूल्यांकन परिवर्तन होना था। तदनुसार, एनआईआईपी-जीडीपी अनुपात जून 2012 के अंत की तुलना में सितंबर 2012 के अंत में कम हो गया (सारणी III.8)। भारत के एनआईआईपी में संकटोत्तर अवधि के दौरान क्रमिक गिरावट हुई क्योंकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवल अंतरराष्ट्रीय देयताएं मार्च 2008 के अंत के 5.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2012 के अंत में 15.3 प्रतिशत हो गई थीं जिसका कारण चालू खाते के घाटे में वृद्धि होना था।

III.19 सारांशतः, भारत के बाह्य ऋण की स्थिरता के संबंध में चिंता बढ़ गई है। सरकार द्वारा घोषित निर्यात संवर्धन के उपायों के दूसरे दौर के बावजूद वैश्विक आर्थिक और व्यापार संबंधी स्थिति में सुधार संबंधी अनिश्चितता भारत के निर्यात को निरंतर प्रभावित कर सकती है। सीएडी को व्यवहार्य पथ पर लाने के लिए भारत के आयात, विशेष रूप से पीओएल और स्वर्ण आयात, की प्रवृत्ति पर सूक्ष्म दृष्टि रखने की आवश्यकता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हाल में की गई नीतिगत घोषणाओं से वैश्विक वित्तीय दबाव कम होने के बावजूद, आर्थिक गतिविधियों में तेजी, जो कि वैश्विक व्यापार की संभावना के लिए आवश्यक है, के लिए समय लग सकता है। भारत की बाह्य मांग में मजबूती लाने के लिए ईएमडीई संबंधी वृद्धि संभावना में सुधार होना जरूरी है। प्रचुर वैश्विक चलनिधि से भारत जैसी अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह बढ़ने की संभावना के बावजूद सीएडी का कम होना आवश्यक है क्योंकि पूंजी प्रवाहों की निरंतरता और सीएडी के तनावमुक्त वित्तपोषण के लिए मजबूत देशी आर्थिक और कारोबारी वातावरण निरंतर बना रहना आवश्यक होगा।

सारणी III.7 : बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता सूचकांक

(प्रतिशत)

सूचकांक	मार्च 2012 के अंत में	जून 2012 के अंत में	सितंबर 2012 के अंत में
1	2	3	4
सकल देशी उत्पाद की तुलना में कुल ऋण का अनुपात*	19.9	21.6	20.7
कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण का अनुपात (मूल परिपक्वता)	22.6	23.1	23.1
कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण का अनुपात (अवशिष्ट परिपक्वता)	42.6	42.9	43.7
कुल ऋण की तुलना में रियायती ऋण का अनुपात	13.9	13.5	13.2
कुल ऋण की तुलना में रिजर्व का अनुपात	85.2	82.9	80.7
रिजर्व की तुलना में अल्पावधि ऋण का अनुपात	26.6	27.8	28.7
कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात #	42.7	42.9	43.7
रिजर्व की तुलना में अल्पावधि ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात #	50.1	51.8	54.1
आयात का रिजर्व कवर (महीनों में)	7.1	7.0	7.2
आयात और ऋण चुकौती सेवा का रिजर्व कवर (महीनों में)	6.8	6.6	6.8
ऋण चुकौती अनुपात (चालू प्राप्तियों की तुलना में ऋण चुकौती सेवा)	6.0	5.8	5.8
बाह्य ऋण (बिलियन अमरीकी डॉलर)	345.4	348.8	365.3

*: वर्तमान बाजार मूल्य पर वार्षिकीकृत जीडीपी

#: आरबीआई अनुमान